The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 4 | Issue 1 | January 2026
ISSN: 2583-973X (Online), SJIF IF: 5.6
Website: www.theacademic.in

भारतीय विदेश नीति : इक्कीसवीं (21वीं) सदी में बदलती वैश्विक परिस्थितियाँ

डॉ. गीता कुमारी

सहायक अध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, आईसेक्ट यूनिवर्सिटी , झारखण्ड

gitakumari3015@gmail.com

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.18714053

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 29-01-2026

Published: 10-02-2026

Keywords:

भारतीय विदेश नीति ,21वीं सदी ,अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा ,परिवर्तन ,संकोच ,आक्रामक ,अग्रसर

ABSTRACT

21वीं सदी में भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों की रक्षा , आर्थिक विकास और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। श्री अटल बिहारी वाजपेई के अंतिम कार्यकाल से लेकर डॉ. मनमोहन सिंह तथा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक भारत की विदेश नीति काफी परिवर्तन के दौर से गुजरी है। अब विश्व पटल पर भारत एक आर्थिक और सैनिक दृष्टि से उभरती हुई महाशक्ति के रूप में दिखाई पड़ता है। वर्तमान में वैश्विक स्तर में कोई भी निर्णय हो तो उसमें भारत की भागीदारी अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। वर्तमान में भारत अपनी विदेश नीति के संबंध में महत्वपूर्ण कठोर निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं करता है। भारत वर्तमान में अपनी दशकों पुरानी सुरक्षात्मक नीति को बदलते हुए अब अधिक स्पष्ट एवं आक्रामक नीति की ओर अग्रसर हो रहा है तथा विश्व पटल पर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अपने महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहा है । वर्तमान भारतीय विदेश नीति भारत को विश्व गुरु का दर्जा वापस दिलाने की तरफ पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है।

परिचय:

भारत की विदेश नीति की झलक संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मिलती है जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि पर आधारित है। भारतीय विदेश नीति का प्रारंभ नेहरू योग से होता है ।नेहरू ही विदेश नीति के निर्माता और मूल निर्धारक थे । 21वीं शताब्दी के वर्षों में भारत की विदेश नीति परिवर्तन के दौर से गुजरी है ।वर्ष

2020 में दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में भारत के विदेश सचिव ने कहा था कि "भारत गुटनिरपेक्षता के अतीत से बाहर निकल चुका है और आज अपने हितों को देखते हुए दुनिया के अन्य देशों के साथ रिश्ते बना रहा है ।" वर्तमान में भारत विश्व के लगभग सभी मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है और बहुपक्षीय संस्थानों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है ।

विदेश नीति का अर्थ :

विदेश नीति राष्ट्रीय हितों ,सिद्धांतों एवं उद्देश्यों का एक जोड़ है। एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित करने ,अंतरराष्ट्रीय मंच पर सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने एवं युद्ध तथा शांति के प्रश्नों में अपनी भूमिका के लिए जो कार्यक्रम और नीतियां अपनाई जाती है यही उस राष्ट्र की विदेश नीति कहलाती है । प्रत्येक देश अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को संचालित करते हेतु विदेश नीति का प्रतिपादन करता है उन्हें अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण के अनुरूप ढालने का प्रयास करता है ताकि वह अन्य देशों के व्यवहार में बदलाव ला सके, उसे प्रभावित कर अपने नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त कर सके।[1]

भारत की विदेश नीति :

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति के बारे में एक प्रेस सम्मेलन सितंबर 1946 में कहां था कि-" वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेग और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देश को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान कराने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा, साथ ही वह दुनिया के शांतिप्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील रहेगा।[2]

यह विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होती है, जैसे -भौगोलिक परिस्थिति ,इतिहास और परंपरा, राजनीतिक संगठन ,राष्ट्रीय नेतृत्व की दृढ़ इच्छाशक्ति ,अंतरराष्ट्रीय स्थिति ,आर्थिक स्थिति, घरेलू परिस्थितियां सैन्य शक्ति, सरकार की संरचना और जनमत आदि।[3]

भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत :

भारतीय विदेश नीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है [4]

1. **गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत :** - गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत भारत के विदेश नीति का केंद्रीय आधार है । विश्व शांति ,शांतिपूर्ण सहयोग और एकता जैसे मूल्यों की पूर्ति इसी सिद्धांत के माध्यम से की जाती है । भारत की विदेश नीति के इस महत्वपूर्ण तत्व के कारण अनेक बार राजनीतिक विश्लेषकों ने भारत की विदेश नीति को ही

गुटनिरपेक्षता की नीति कहकर संबोधित किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के उपरांत यह सिद्धांत समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों की एक महत्वपूर्ण यथार्थता और भारत की विदेश नीति की एक विशेष पहचान बन गया । इस सिद्धांत का मूल आशय है कि यह नीति सदैव सैया गुटों से दूर रहकर स्वतंत्र मानसिकता के साथ विश्व शांति के लिए सक्रिय प्रयास करने वाली शक्तियों का दृढ़ विरोध करती है। भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी भी बड़े सैन्य गुट में शामिल न होने की नीति अपनाई जो आज भी प्रासंगिक है ।

2.पंचशील सिद्धांत - यह भारत की विदेश नीति का आधार है ,जिसमें पांच सिद्धांत शामिल हैं –

(a) एक- दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान

(b) एक -दूसरे पर आक्रमण न करना

(c) एक- दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना

(d) समानता और पारस्परिक लाभ

(e) शांतिपूर्ण सह -अस्तित्व

3. विश्व शांति और सुरक्षा- - भारत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने और उसका समर्थन करने के लिए काम करता है ।

4. उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद ,और नस्लवाद का विरोध - भारत औपनिवेशिक शासन, साम्राज्यवाद और नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों का विरोधी है ।

5. अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान- भारत अंतरराष्ट्रीय कानूनो , संधियों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को महत्व देता है।

6. राष्ट्रीय हितों का संरक्षण - भारत अपनी विदेश नीति में अनेक राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और संवर्धन को प्राथमिकता देता है ।

7. निरस्त्रीकरण - भारत परमाणु अप्रसार और निशस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में वैश्विक प्रयासों का समर्थन करता है ।

8.गुजराल सिद्धांत - 1996 में केंद्र में 13 राजनीतिक दलों की संयुक्त सरकार बनने के बाद 1997 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इंद्र कुमार गुजराल ने शपथ ली । उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने हेतु

जो प्रयास किए , वे 'गुजरात सिद्धांत' के नाम से प्रसिद्ध हुए l इस सिद्धांत के अंतर्गत भारत ने सन 1997 में बांग्लादेश के साथ गंगा जल बंटवारे के मुद्दे को शांतिपूर्वक सुलझाया l इसी प्रकार भारत ने चीन के साथ भी शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने के दिशा में प्रयास किए। इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने हेतु गुजराल सरकार ने पड़ोसी देशों की जनता के प्रति सौहार्द पूर्ण संदेश भेजें। भारत ने अमेरिका के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया । भारत ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने हेतु अनेक सकारात्मक घोषणाएं भी की। बाद में अटल बिहारी वाजपेई जी ने भी इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया ।

9. वसुधैव कुटुंबकम - भारत "दुनिया एक परिवार है " के सिद्धांत में विश्वास करता है जो सभी के साथ सद्भाव और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है ।

भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य :

भारत की विदेश नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं 5

* किसी भी अन्य देश के समान ही भारत के विदेश नीति का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य अपने ' राष्ट्रीय हितों ' की रक्षा करना एवं तीव्र परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर नजर रखना ,जिससे कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ कदम से कदम मिलाकर चला जा सके l

* आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान को सहयोग व समर्थन देना, सीमापार आतंकवाद को समाप्त करना तथा पाकिस्तान में कार्यरत आतंकवादी ढांचे को समाप्त करना ।

*भारत के तीव्र आर्थिक विकास एवं वैश्विक निवेश को बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय माहौल को विकसित करना, देश में विज्ञान

एवं तकनीकी तथा प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाले अंतरराष्ट्रीय समझौता को संपन्न करना l

*भारत द्वारा ' लुक ईस्ट ' नीति के स्थान पर ' एक्ट ईस्ट' नीति को अपनाकर आसियान के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करना l

* पी -5 समूह के देशों के साथ घनिष्ठता से कार्य करना तथा विश्व की महाशक्तियों जैसे - अमेरिका ,रूस ,यूरोपीय संघ ,जापान ,फ्रांस ,जर्मनी एवं चीन आदि के साथ सामरिक समझौते करना ।

* विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीयों को जोड़ना तथा उनके हितों की रक्षा करना ।

* विकसित एवं विकासशील देशों में समान आर्थिक ,राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देना ।

* क्षेत्रीय संगठनों जैसे- सार्क, ब्रिक्स, बिम्सटेक ,आईबीएसए ,आईओआर -एआरसी, मैकांग- गंगा सहयोग, G-20, G-7 तथा यूरोपीय संघ के साथ सहयोगपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना 1

नए युग में भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं :

- भारत किसी विशेष देश के विरुद्ध किसी अन्य देश या देशो के समूह द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने का समर्थन नहीं करता है जब तक कि वे प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय सर्वसम्मति के साथ न अधिरोपित किया जाए ।
- भारत अन्य देशों के आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी करने में विश्वास नहीं रखता, परंतु यदि कोई देश अनजाने में या जानबूझकर भारत के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करता है तो भारत बिना समय बर्बाद किए हस्तक्षेप करने में नहीं झिझकेगा ।
- भारत की वर्तमान विदेश नीति की सबसे खास विशेषता यह है कि इसमें पूर्व की नीतियों की अपेक्षा जोखिम लेने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है । भारत अपनी दाशको पुरानी सुरक्षात्मक विदेश नीति को बदलते हुए कुछ हद तक आक्रामक विदेश नीति की ओर अग्रसर हो रहा है।
- 2016 में उरी आतंक हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और वर्ष 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक तथा 2017 के डोकलाम में भारत की चीन के खिलाफ कार्रवाई तथा 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर भारतीय विदेश नीति के आक्रामक और सख्त होने के होने के प्रमुख उदाहरण हैं ।
- भारत ने अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है और अमेरिका तथा रूस के साथ भारत के संबंध इस तथ्य के प्रमुख उदाहरण हैं ।

21वीं शताब्दी में भारत की विदेश नीति में परिवर्तन

भारत के विदेश नीति के 21वीं शताब्दी में एक नए युग में प्रवेश करने के साथ ही बदलाव दिखाई पड़ता है । पिछले दो दशकों के दौरान भारतीय विदेश नीति में काफी परिवर्तन हुआ है । दशकों पुरानी सुरक्षात्मक विदेश नीति के स्थान पर अब अधिक स्पष्ट एवं आक्रामक संतुलित तथा विश्व पटल पर उभरती हुई महाशक्ति की नीति के रूप में दृष्टिगोचर होती है नई सादी में भारत की विदेश नीति को समझने के लिए इसे तीन चरणों में विभाजित करते हैं - प्रथम चरण - श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की भारतीय विदेश नीति , द्वितीय चरण - डॉ. मनमोहन सिंह सरकार की भारतीय विदेश नीति तथा तृतीय चरण - श्री नरेंद्र मोदी सरकार की वर्तमान में भारतीय विदेशनीति ।

प्रथम चरण : श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की भारतीय विदेश नीति (1998-2004)

1999 में हुए आम चुनाव के बाद भारत में एनडीए की सरकार बनी जिसमें बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी मुख्य राजनीतिक दल के रूप में तथा इसके नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने 1 अटल जी के कार्यकाल के दौरान विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत को परमाणु संपन्न शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बनाने में था । उनके नेतृत्व में 11 मई तथा 13 मई 1998 को पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया । भारतीय विदेश नीति के इतिहास में पहली बार परमाणु- सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया । श्री वाजपेई ने कहा कि भारत पूर्ण - निशस्त्रीकारण को अपना पूर्ण समर्थन देता रहेगा किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधन की नीति को कायम रखेगा। वाजपेई सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अपनी पूर्ववर्ती सरकारों के फैसलों के अनुरूप बिना राष्ट्रीय सहमति के CTBT एवं FMCT पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे I

अटल बिहारी वाजपेई के कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ संबंधों को मधुर बनाने के लिए ' लाहौर घोषणा - पत्र (1999)' एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। वर्ष 2000 में भारत एवं अमेरिका संबंध 21वीं शताब्दी के दृष्टिकोण का घोषणा -पत्र नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए । सितंबर 2000 में अटल जी ने अमेरिका की यात्रा की तथा वे कांग्रेस की 106 वीं संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री तथा एकमात्र विदेश मंत्री नेता बन गए । वाजपेयी कार्यकाल के दौरान वर्ष 2000 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत और रूस के मध्य रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए । सितंबर 2001 के बाद भारतीय विदेश नीति में "आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध" में अमेरिका का सहयोग करने का निर्णय लिया गया 1 भारत ने पूरी दुनिया को यह बताने का प्रयत्न किया वह विगत दो दशकों से सीमापार आतंकवाद से प्रभावित है इसलिए भारतीय विदेश नीति में आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा ।6 अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2001 में भारत के ऊपर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए । अटल जी की विदेश नीति के अंतर्गत 21वीं सदी की शुरुआत में भारत तथा पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध यूरोपियन संघ एवं फ्रांस ,जर्मनी, इटली ,ब्रिटेन व कई अन्य यूरोपियन देशों के साथ आर्थिक और सामाजिक तथा सामरिक समझौते हुए। इसी प्रकार पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीकन देशों के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते हुए जिसके द्वारा भारत विश्व स्तर पर एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के साथ-साथ दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र होने के कारण अग्रणी पंक्ति के देशों में खड़ा हो गया । इसी कारण भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक मंचों में भागीदारी की तथा इसके पुनर्गठन की वकालत की । भारत के इस आहवान का संयुक्त संघ के अनेक प्रतिनिधियों ने समर्थन किया । अनेक राष्ट्र इस बात पर भी सहमत दिखे कि भारत के आकार, लोकतंत्र के प्रति इसके बेदाग रिकॉर्ड ,मजबूत आर्थिक संभावनाओं तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति कार्यों में योगदान को देखते हुए भारत सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य बनने के लिए उपयुक्त है ।7

इस्लामाबाद में 4- 6 जनवरी 2004 को आयोजित 12 वें सार्क शिखर सम्मेलन में दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) से सम्बद्ध एक करार संपन्न हुआ। इसी दौरान भारत का वर्ष 2004-06 अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य के रूप में चयन हुआ ।8

द्वितीय चरण :डॉ. मनमोहन सिंह सरकार की भारतीय विदेश नीति (2014-2014)

2004 में डॉ.मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यू.पी.ए की सरकार बनी तथा इस सरकार ने भी एन.डी.ए सरकार की विदेश नीति को ही आगे बढ़ाया l इस सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में भारत तथा अमेरिका के मध्य सिविल परमाणु समझौता है l वर्ष 2001 के उपरांत भारत एवं अमेरिका के मध्य संबंध तेजी से आगे बढ़े और इसी क्रम में वर्ष 2005 में भारत और अमेरिका के मध्य "सिविल परमाणु समझौता" हुआ जो भारत और अमेरिका के मध्य बढ़ते सामरिक संबंधों का परिणाम था । इस समझौते से भारत को समूचे विश्व में उत्तरदायी राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हो गया और भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु अप्रसार संधि तथा सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किये बगैर भी उसे परमाणु तकनीकी और परमाणु ईंधन प्राप्त हो रहे हैं।9

वर्ष 2005 में "पश्चिम की ओर देखो नीति" अपनाई गई lवर्ष 2008 में अमेरिका भारत के मध्य के परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर होकर लागू होने के साथ ही भारत का परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के साथ परमाणु व्यापार एवं सहयोग की अनुमति मिलने के कारण कई अन्य परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के साथ समझौते संपन्न हुए । भारत के साथ सामरिक परमाणु समझौते- जर्मनी ,रूस ,यूरोपीय यूनियन ,जापान, दक्षिण कोरिया ,अफगानिस्तान, फ्रांस ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका के साथ हुए हैं। वर्ष 2008 के बाद विश्व में व्याप्त आर्थिक मंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था और विदेश नीति प्रभावित हुई। भारत ने इस बिंदु पर बल दिया कि विश्व अर्थव्यवस्था के प्रबंध में विकासशील देशों की भूमिका में वृद्धि होनी चाहिए । वर्ष 2010 में सुरक्षा परिषद के सभी पांचो स्थाई सदस्यों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत की यात्रा की जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा उल्लेख अत्यधिक उल्लेखनीय है ।अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता हेतु भारत का समर्थन किया और कहा कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है।10

भारत- आसियान के मध्य दिसंबर 2012 में नई दिल्ली में आयोजित भारत -आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। तेहरान में 2012 में आयोजित 16 वें शिखर सम्मेलन में डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2012 में भारत ने))सीरिया, दक्षिणी सूडान, सोमालिया और फिलिस्तीन में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद एवं जलदस्युओं के खिलाफ सैन्य कार्रवाई व शांति सेना के रूप में मदद तथा जलवायु परिवर्तन के मुद्दे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और सेना का अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग करने, अपनी

संप्रभुता की रक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उद्देश्य को मध्यनजर रखते हुए अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाया। इनके कार्यकाल में भारतीय विदेश नीति के रूप में पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों को कायम रखने पर जोर दिया गया।11

तृतीय चरण: श्री नरेंद्र मोदी सरकार की भारतीय विदेश नीति (2014 से वर्तमान तक)

16वें लोकसभा चुनाव (मई, 2014) में पहली बार 1884 के बाद केंद्र में किसी एक दल के नेतृत्व में सरकार का निर्माण हुआ और पहली बार भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ जिसका प्रभाव विदेश नीति में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । 16वीं तथा 17वीं लोकसभा में भाजपा के पूर्ण बहुमत के कारण श्री नरेंद्र मोदी का एक लोकप्रिय और शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय विदेश नीति को नेतृत्व मिला । 21वीं शताब्दी में श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है । 2014 के बाद भारतीय विदेश नीति के निर्णय शीघ्रता से लिए जा रहे हैं तथा विदेश नीति का स्वरूप स्पष्ट ,आक्रामक और शक्तिशाली दिखाई पड़ता है इसी कारण से वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत एक उभरती हुई महाशक्ति तथा शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है । भारतीय विदेश नीति के आक्रामक और शक्तिशाली होने का श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को जाता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

- **पहले पड़ोस की नीति :** पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अपने शपथ ग्रहण समारोह में दक्षेस के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया । प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा भारत के सबसे छोटे पड़ोसी देश भूटान के लिए निर्धारित की गई । प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में नेपाल , श्रीलंका एवं बांग्लादेश की यात्राएं की गई और बांग्लादेश के साथ अत्यधिक महत्वपूर्ण सीमा समझौता किया गया, जो वर्ष 1974 से लंबित था। वर्ष 1996 में गुजराल सिद्धांत द्वारा निर्मित इस नीति को प्रभावी रूप से लागू करने का प्रयत्न वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है ।12
- **एक्ट ईस्ट पॉलिसी :** 'पूर्व की ओर देखो' की नीति भारत के द्वारा वर्ष 1992 में अपनाई गई, परंतु इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन में अनेक प्रकार की बाधाएं बनी हुई है इसलिए आधारभूत संरचना के बेहतर विकास के द्वारा आसियान देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने पर बल दिया जा रहा है तथा दक्षिण कोरिया और जापान जैसे पूर्व में स्थित देश के साथ संबंधों को बेहतर करने की रणनीति अपनाई जा रही है । इसलिए 'लुक ईस्ट पॉलिसी' की जगह 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। इस संदर्भ में भारत के 69 में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2018) के अवसर पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड समारोह में आसियान के 10

देशों के राष्ट्र प्रमुखों और शासनाध्यक्षों ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया । यह आसियान देशों के साथ भारत के गहरे होते संबंधों और भारत के प्रभाव के महत्व को दर्शाता है । 13

- **आर्थिक विकास :** भारत को विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा 'मेक इन इंडिया' का नारा दिया गया तथा भारत को विश्व के निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयत्न किया गया है। भारत का तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 'डिजिटल इंडिया' , स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं के द्वारा उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति के रूप में खाका पेश किया गया है। हाल ही में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के समय देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्थिक घोषणाओं के साथ 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की 12 मई 2020 को शुरुआत की गई है जो भारत का आर्थिक क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है ।
- **संस्कृतिक कूटनीति :** सांस्कृतिक कूटनीति पहले भी अपनाई गई थी परंतु इसका प्रभावी प्रयोग वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की यात्रा के लिए क्योटो शहर का चुनाव किया और वाराणसी तथा क्योटो के बीच बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री द्वारा म्यांमार यात्रा के दौरान भी सांस्कृतिक संबंधों के द्वारा आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ किया गया। भारत द्वारा पहली बार योग दिवस का सार्वजनिक आयोजन किया गया और समूचे विश्व में योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित हुए जो भारत के सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में सहायक है । भारत सरकार की पहल पर 11 दिसंबर 2014 को 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' के 69 वें सत्र के दौरान एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस / विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए मान्यता दी गई ।
- **अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा :** वर्तमान में भारत सरकार की विदेश नीति का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना एवं परिवर्तित अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर नजर रखना, जिससे कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ कदम से कदम मिलाकर चला जा सके । आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान को सहयोग व समर्थन देना, सीमापार आतंकवाद को समाप्त करना तथा पाकिस्तान में कार्यरत आतंकवादी ढांचे को समाप्त करना जैसे कठोर कदम हाल ही में भारत द्वारा उठाए गए हैं । वर्ष 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, वर्ष 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, वर्ष 2017 में डोकलाम में भारत की चीन के खिलाफ कार्रवाई तथा 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकी हमले के खिलाफ भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का चलाया जाना तथा हाल ही में लद्दाख में चीन के खिलाफ कार्रवाई भारतीय विदेश नीति के आक्रामक और सख्त होने के प्रमुख उदाहरण हैं 1 चीनी सामान का बहिष्कार तथा स्वदेशी अपनाने पर जोर ,संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी सदस्यता के लिए अधिकांश देशों का समर्थन हासिल करना, अमेरिका, रूस,फ्रांस तथा अन्य देशों के साथ रक्षा समझौते करना, वन नेशन वन पेंशन योजना, सैन्य एकीकरण करते हुए "चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ" की स्थापना, जम्मू और कश्मीर से

अनुच्छेद 370 को समाप्त करके संपूर्ण भारत में एक विधान, एक संविधान तथा एक राष्ट्रीय झंडा के सपने को साकार करना, जैसे अनेक महत्वपूर्ण फैसले लेना और कठोर आर्थिक व दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ नीतिगत फैसलो के निर्णय लेकर क्रियान्वित करना नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति के सुदृढ़, मजबूत, सशक्त और आक्रामक विदेश नीति को दर्शाता है 1

- **अन्य :** विश्व के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उत्कृष्ट व्यक्तित्व के कारण बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, मालदीव ,फिलिस्तीन, दक्षिण कोरिया, रूस आदि देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है । प्रधानमंत्री मोदी की कुशल विदेश नीति के कारण उन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान "चैंपियन ऑफ द अर्थ" से नवाजा गया है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा उन्हें "ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड" से सम्मानित किया गया है ।15

निष्कर्ष : निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि 21वीं शताब्दी में बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की विदेश नीति में काफी परिवर्तन हुआ है । श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम कार्यकाल से लेकर डॉ. मनमोहन सिंह तथा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक भारत की विदेश नीति काफी परिवर्तन के दौर से गुजरी है । वर्तमान भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करते हुए बेझिझक निर्णय लेती है तथा विश्व पटल पर भारत एक आर्थिक और सैन्य दृष्टि से भी उभरती हुई महाशक्ति के रूप में दिखाई पड़ता है। वर्तमान में वैश्विक संदर्भ में कोई भी निर्णय हो तो उसमें भारत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है । वर्तमान में भारत विदेश नीति के संबंध में महत्वपूर्ण कठोर निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं करता है । चाहे परमाणु परीक्षण करना हो या आतंकवाद के खिलाफ सीमापार जाकर सैन्य कार्रवाई करना हो जैसे निर्णय यह सिद्ध करते हैं कि 21वीं शताब्दी में भारत की विदेश नीति पहले से कहीं अधिक मजबूत , स्पष्ट, सुदृढ़ और सशक्त तथा परिवर्तन की ओर अग्रसर विदेश नीति दिखाई पड़ती है।

संदर्भ सूची :

- जैन बी.एम. : अंतरराष्ट्रीय संबंध, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2013 ,पृष्ठ संख्या -249
- सिंघल ,एस.पी. : अंतरराष्ट्रीय राजनीति, शालीमार पब्लिशिंग हाउस, वाराणसी, 1986 ,पृष्ठ संख्या- 110
- खन्ना बी. एन. अरोड़ा लिपाक्षी कुमार : भारत की विदेश नीति, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि. नोएडा, पांचवा संस्करण 2019 ,पृष्ठ संख्या -8
- लक्ष्मीकांत, एम. : भारत की राजव्यवस्था, मेक्ग्रा हाई एजुकेशन (इंडिया) प्रा. लि., 2015 ,पृष्ठ संख्या- 70.1-70.3
- लक्ष्मीकांत, एम. : उपर्युक्त ,पृष्ठ संख्या -70.4

- मिश्रा, राजेश : राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन, ओरिएंट ब्लैकस्वान प्रा. लि., हैदराबाद ,2020,पृ.सं. 384
- वार्षिक रिपोर्ट : 2000 - 2001, विदेश मंत्रालय भारत सरकार, पृ. सं. 9-10
- वार्षिक रिपोर्ट : 2003-04, विदेश मंत्रालय भारत सरकार, पृ. सं.-4-9
- मिश्रा, राजेश : उपर्युक्त पृ. सं. 384
- मिश्रा, राजेश : उपर्युक्त पृ. सं. 385
- वार्षिक रिपोर्ट 2012-13, प्रस्तावना और सारांश, विदेश मंत्रालय भारत सरकार, पृ. सं.3,10,11
- मिश्रा, राजेश : उपर्युक्त पृ. सं. 386
- एचटीटीपीएस डब्ल्यू.डब्ल्यू.जीअओवी.इन : 26 जनवरी 2018
- मिश्रा, राजेश : उपर्युक्त पृ. सं. 386-387
- न्यूज़ 18 हिंदी : 25 सितंबर 2019